भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **- 2122**
दिनांक **31.07.2026** को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्लोबल साउथ के देशों के साथ जुड़ाव

2122. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने कूटनीतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोई नई विकास सहायता, क्षमता-निर्माण या प्रौद्योगिकी-साझाकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हाँ, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पहलों से भारत की वैश्विक स्थिति और रणनीतिक हितों को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की उम्मीद है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह**)**

(क) भारत ने बहुपक्षीयता को मजबूत करने और ग्लोबल साउथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से महत्वपूर्ण पहल की है। अपनी जी20 अध्यक्षता के दौरान, भारत ने वसुधैव कुटुम्बकम में निहित 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' विषय पर दिनांक 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत की पहल पर, अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया, जो प्रमुख वैश्विक शासन मंचों में ग्लोबल साउथ प्रतिनिधित्व का एक ऐतिहासिक विस्तार है। भारत ने विकासशील देशों के लिए दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने हेतु एक विशिष्ट मंच के रूप में वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट (वीओजीएसएस) की शुरूआत की, जिसके तीन संस्करण (जनवरी 2023, नवंबर 2023, अगस्त 2024) आयोजित किए गए और प्रत्येक संस्करण में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया और प्रशांत द्वीपों के 100 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई। प्रथम वीओजीएसएस से प्राप्त होने वाले इनपुट ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर परिणामों को तैयार करने में योगदान दिया।

विशेष रूप से, 'दक्षिण' (विकास एवं ज्ञान साझाकरण पहल) की स्थापना विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझा करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है, जिसका गठन पहले ' वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' (जनवरी 2023) में 'ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के एक भाग के रूप में किया गया था। यह विकास सहयोग के लिए साझेदारी-आधारित दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है।

(ख) भारत हमेशा साथी विकासशील देशों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है और ग्लोबल साउथ के देशों के समग्र मानव-केंद्रित विकास के कारण का रचनात्मक रूप से समर्थन करता रहा है। भारत सरकार ने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

- विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवसंरचना विकास से लेकर समुदाय से संबंधित परियोजनाओं तक, जिनमें स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण और शिक्षा शामिल हैं, परियोजनाओं को क्रियान्वित करके कनेक्टिविटी (संपर्क) और आर्थिक अंतर्संबंधों को बढ़ाना।
- आर्थिक चुनौतियों को कम करने और संकट से उबरने में सहायता के लिए भागीदार देशों को वित्तीय, बजटीय और मानवीय सहायता का विस्तार करना। छात्रों और पेशेवरों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके ग्लोबल साउथ में क्षमता निर्माण और कौशल विकास में योगदान करना।
- भारत ग्लोबल साउथ के लिए विकास वित्त का एक बड़ा प्रदाता और फिनटेक क्षेत्र सहित प्रौद्योगिकी परिनियोजन के लिए एक मॉडल बना हुआ है।

(ग) इन पहलों ने भारत को न केवल भागीदार देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और अपना दृष्टिकोण रखने में सक्षम बनाया है, लेकिन वैश्विक मुद्दों जैसे कि सुधारित बहुपक्षीयता, शांति और सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर एजेंडे को भी आकार दिया है। इन पहलों का उपयोग न केवल भारत के लिए किया गया है, बल्कि सभी के लिए विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की आवाज के रूप में भी किया गया है।

*****